भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5721

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक का घरेलू उत्पादन

5721. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में पुनर्जीवित/कार्यान्वित उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ओडिशा स्थित तालचेर उर्वरक संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों के आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों के लिए दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु घरेलू उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने देश के पूर्वी और जनजातीय क्षेत्रों में सब्सिडी वाले उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में उक्त पहलों के प्रभाव के संबंध में ओडिशा सहित राज्य-वार कोई आकलन किया है;
(घ) ओडिशा के कंधमाल जैसे दूरस्थ जिलों में उर्वरक वितरण और भंडारण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ड.) क्या सरकार का संतुलित उर्वरीकरण और सतत् कृषि विकास सुनिश्चित करने हेतु नैनो डीएपी जैसे नवोन्मेषी उर्वरकों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(ख) से (घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड

(एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। रामगुंडम, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने क्रमशः 22.03.2021, 07.12.2021, 18.10.2022 और 05.11.2022 को यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। 28.02.2026 तक टीएफएल परियोजना की समग्र प्रगति 71.24% है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसें असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए, दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) उर्वरक विभाग ने एमआरपी की उपयुक्तता सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 18.01.2024 से दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ii) प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।

(iii) एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड कर दी गई है।

(iv) मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी जो स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एसएसपी पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से अनुमोदित की गई है।

उपरोक्त कदमों ने पी एंड के उर्वरकों (डीएपी और एसएसपी सहित) के उत्पादन को 2014-2015 में 159.54 एलएमटी से बढ़ाकर 2024-2025 में 211.22 एलएमटी करने में मदद की है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
ii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;
iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
v. राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, चल रहे रबी 2025-26 के दौरान ओडिशा राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त सीजन के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

रबी मौसम 2025-26 (22.03.26 तक) के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़ें एलएमटी में

क्र.सं.	**उत्पाद**	**ओडिशा**		
		आवश्यकता	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**
1	**यूरिया**	1.78	3.24	1.75
2	**डीएपी**	0.72	1.38	0.75
3	**एमओपी**	0.24	0.53	0.19
4	**एनपीकेएस**	0.86	1.58	0.74

इसके अलावा, उर्वरकों के संबंध में भंडारण व्यवस्था और क्षमता की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों और उर्वरक कंपनियों द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, उर्वरक वितरण को सुदृढ़ करने के लिए, उर्वरकों को पर्याप्त रेक देने, प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए समय पर रेक निकालने के लिए उर्वरक विभाग और रेल मंत्रालय के बीच नियमित समन्वय है।

(ङ.): देश भर के किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. नैनो उर्वरकों के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविरों, वेबिनार, क्षेत्रीय प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

ii. नैनो उर्वरक संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

iii. नैनो उर्वरकों को उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से जारी मासिक आपूर्ति योजना के तहत शामिल किया गया है।

iv. पर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से नैनो यूरिया जैसे उर्वरकों के सहज अनुप्रयोग और उपयोग के लिए, 'किसान ड्रोन' जैसे अभिनव छिड़काव विकल्प और खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बैटरी संचालित स्प्रेयर के वितरण जैसी पहल की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग छिड़काव सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

v. उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के सहयोग से परामर्श और क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शनों के माध्यम से देश के सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी को अपनाने के लिए एक महा अभियान शुरू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के मार्गदर्शन और आईसीएआर-कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की देखरेख में, इफको ने खरीफ और रबी 2024-25 के दौरान 2,500 नैनो डीएपी किसान फील्ड परीक्षण और खरीफ और रबी 2025-26 के दौरान 2,938 नैनो डीएपी किसान फील्ड परीक्षण (23.03.2026 तक) देश के 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों (एसीजेड) में आयोजित किए थे।

vi. इसके अलावा, उर्वरक विभाग ने उर्वरक कंपनियों के सहयोग से देश के 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शनों और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अभियान भी शुरू किया है। इफको ने खरीफ और रबी 2024-25 के दौरान 448 नैनो यूरिया किसान फील्ड परीक्षण और खरीफ और रबी 2025-26 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के मार्गदर्शन में और आईसीएआर-कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की देखरेख में देश के 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों (एसीजेड) में 484 नैनो यूरिया किसान फील्ड परीक्षण (23.03.2026 तक) आयोजित किए थे।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की राज्यवार बिक्री निम्नानुसार है:

नैनों यूरिया की सुरुआत से (अगस्त 2021) से 28.02.2026 तक राज्यवार बिक्री (प्रत्येक 500 मिलीलीटर की लाख बोतलों में)			
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**उत्पादन**	**बिक्री**
1	अंडमान और निकोबार	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6.2574	23.6863
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	0	44.70921
5	बिहार	0	75.15178
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	27.61882
8	दादरा और नगर हवेली	0	0
9	दमन और दीव	0	0
10	दिल्ली	0	0
11	गोवा	0	0
12	गुजरात	880.72649	96.27461
13	हरियाणा	0	57.73399
14	हिमाचल प्रदेश	0	7.45937
15	जम्मू और कश्मीर	0	10.2962
16	झारखंड	0	15.75299
17	कर्नाटक	19.94884	69.9491
18	केरल	0	4.38858
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	97.39114
21	महाराष्ट्र	0	108.2609
22	मणिपुर	0	0.00804
23	मेघालय	0	0
24	मिज़ोरम	0	0.00528
25	नागालैंड	0	0
26	ओडिशा	0	36.09214
27	पुडुचेरी	0	0
28	पंजाब	9.8808	102.3392
29	राजस्थान	0	101.28046
30	सिक्किम	0	0
31	तमिलनाडु	0	41.38483
32	तेलंगाना	0	30.24062
33	त्रिपुरा	0	0.00126
34	उत्तराखंड	0	8.58652
35	उत्तर प्रदेश	547.32283	171.40733
36	पश्चिम बंगाल	0	89.24858
कुल योग		**1464.13636**	**1219.26725**

नैनों डीएपी की सुरुआत से (मार्च 2023) से 28.02.2026 तक राज्यवार बिक्री (प्रत्येक 500 मिलीलीटर की लाख बोतलों में)			
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**उत्पादन**	**बिक्री**
1	अंडमान और निकोबार	0	0
2	आंध्र प्रदेश	159.89824	26.53388
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	0	4.02941
5	बिहार	0	11.488345
6	चंडीगढ़	0	0
7	छतीसगढ़	0	8.52221
8	दादरा और नगर हवेली	0	0
9	दमन और दीव	0	0
10	दिल्ली	0	0
11	गोवा	0	0
12	गुजरात	219.24157	18.52859
13	हरियाणा	0	5.43879
14	हिमाचल प्रदेश	0	0.42667
15	जम्मू और कश्मीर	0	1.11054
16	झारखंड	0	1.826805
17	कर्नाटक	0	31.89003
18	केरल	0	0.717105
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	38.352075
21	महाराष्ट्र	0	58.22202
22	मणिपुर	0	0.00012
23	मेघालय	0	0
24	मिज़ोरम	0	0.00072
25	नागालैंड	0	0
26	ओडिशा	0	11.1583
27	पुडुचेरी	0	0.13618
28	पंजाब	33.95856	12.62558
29	राजस्थान	0	27.4277
30	सिक्किम	0	0
31	तमिलनाडु	0	10.55304
32	तेलंगाना	0	17.44619
33	त्रिपुरा	0	0
34	उत्तराखंड	0	2.099
35	उत्तर प्रदेश	17.66631	56.463535
36	पश्चिम बंगाल	0	26.9842
कुल योग		**430.76468**	**371.98104**

पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, पोषक तत्वों के नुकसान और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और कम उर्वरक निवेश के साथ फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए नैनो-उर्वरकों, नियंत्रित-रिलीज़ उर्वरकों और फोर्टिफाइड उर्वरकों जैसे उन्नत उर्वरकों की आवश्यकता है। आईसीएआर पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार, उर्वरक नुकसान को कम करने और टिकाऊ फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए नियंत्रित-रिलीज़ होने वाले उर्वरकों, अनुकूलित / फोर्टिफाइड उर्वरकों, जैव उर्वरकों और मृदा-परीक्षण-आधारित पोषक तत्व प्रबंधन प्रौद्योगिकियों (जैसे एसटीसीआर-आईपीएनएस) के विकास और प्रचार में लगा हुआ है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से "भारत के विविध कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में फसल उत्पादकता और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता पर नैनो यूरिया का मूल्यांकन" नामक एक नेटवर्क परियोजना पांच वर्षों के लिए शुरू की गई है ताकि देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में फसल उपज, उत्पादन गुणवत्ता और मिट्टी के पोषक तत्वों के संतुलन के साथ-साथ पौधे के चयापचय में नैनो उर्वरक से पोषक तत्वों के कार्य तंत्र पर दीर्घकालिक अनुप्रयोग के बारे में बेहतर समझ हो सके। इसके अलावा, आईसीएआर बेहतर और टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, फसल विविधीकरण की सिफारिश करता है।

****